मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने "राइज़िंग राजस्थान" ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत नई दिल्ली में हुई इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित किया। इस दौरान 8 लाख करोड़ रु. के एम.ओ.यू. भी साइन हुए।

केवल एम.ओ.यू. नहीं करेंगे, परियोजनाओं को धरातल पर उतारेंगे- भजनलाल

राइज़िंग राजस्थान के दिल्ली रोड शो में 8 लाख करोड़ रूपए के एम.ओ.यू. साइन हुए

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल एक अक्टूबर को केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ कॉनक्लेव तथा प्रमुख देशों के राजनयिकों के साथ राउन्डटेबल में भाग लेगा।**
- **दिल्ली में ऊर्जा, पावर, ट्रांसमिशन, तेल और गैस, सी.एन.जी., लॉजिस्टिक्स तथा एग्रोटेक आदि क्षेत्रों में टाटा पावर, इण्डियन ऑयल, अवाडा ग्रुप, एन.एच.पी.सी, रियायंस बायो एनर्जी, टॉरेंट पावर, स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, महिन्द्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड, टी.एच.डी.सी. इंडिया, ऑयल इण्डिया, ज़िन्दल रिन्यूएबल पावर, एस्सार रिन्यूएबल्स, इन्द्रप्रस्थ गैस, अडानी लॉजिस्टिक तथा जे.के. सीमेण्ट के साथ एम.ओ.यू. किये गये।**

नई दिल्ली, 30 सितंबर। "राइज़िग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024" के तहत आज देश की राजधानी नई दिल्ली में 'इन्वेस्टर मीट' का आयोजन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में किया गया। 'इन्वेस्टर मीट' के दौरान राजस्थान में निवेश के लिए राज्य सरकार के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और विभिन्न कंपनियों के बीच 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। आज हुए एमओयू के साथ, प्रदेश में निवेश के लिए किए गए एमओयू का कुल मूल्य 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो 2047 तक राज्य को 'विकसित राजस्थान' में बदलने के राजस्थान सरकार के प्रयासों में निवेशक और व्यापार समुदाय के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।

दिल्ली में आयोजित इस 'इन्वेस्टर मीट' में मुख्यमंत्री शर्मा के अलावा राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा और राजस्थान सरकार के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

इस 'इन्वेस्टर मीट' में उद्योग एवं व्यापार जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं और इस दौरान अक्षय ऊर्जा, पावर ट्रांसमिशन, तेल और गैस, सीएनजी, लॉजिस्टिक्स, एग्रोटेक जैसे कई क्षेत्रों में निवेश के लिए एम.ओ.यू. हुए। प्रदेश में निवेश के लिए जिन प्रमुख कंपनियों और औद्योगिक समूहों ने सरकार के साथ एमओयू किया, उनमें टाटा पावर, इंडियन ऑयल, अवाडा ग्रुप, एनएचपीसी, रिलायंस बायो एनर्जी, टॉरेंट पावर, स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया, ऑयल इंडिया, जिंदल रिन्यूएबल पावर, एस्सार रिन्यूएबल्स, इंद्रप्रस्थ गैस, अडानी लॉजिस्टिक्स, जेके सीमेंट, बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

इस दौरान, देशी-विदेशी निवेशकों, उद्योग और व्यापार जगत के दिग्गजों, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और अन्य संबंधित स्टेकहोल्डर्स को राज्य में निवेश करने और 9-10-11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024" में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया।

निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, राजस्थान एक परिवर्तनकारी युग की दहलीज पर खड़ा है और विकास और समृद्धि के लिए हमने एक नए दृष्टिकोण को अपनाया है। हमारी सरकार अगले पाँच वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करते हुए 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक भूमि के अधिग्रहण और विकास को सरल बनाया गया है और निजी औद्योगिक पार्क योजना और लैंड एग्रीगेशन एंड मॉनटाइज़ेशन पॉलिसी जैसी पहलें शुरू की जा रही हैं, ताकि कारोबारियों को अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार का ध्यान केवल निवेश संबंधी एमओयू करने पर नहीं है, बल्कि उन्हें धरातल पर लाकर परियोजनाओं में बदलना है।

इस अवसर पर बोलते हुए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां राजस्थान न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो, बल्कि समावेशी और सतत विकास के लिए एक मानक भी स्थापित करे। मैं सभी निवेशकों से राजस्थान आने का आव्हान करता हूं। हमारे राज्य में निवेश करके, आप हमारे प्रचुर संसाधनों और स्ट्रेटैजिक लोकेशन का उपयोग करके मजबूत सप्लाई चेन और सहयोगी उपक्रम बना सकते हैं।

इस अवसर पर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा, यह इन्वेस्टमेंट समिट अगले 5 वर्षों में राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत है। राज्य में निवेश करने का यह उपयुक्त समय है।

इस अवसर पर उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने एक प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि राजस्थान दिल्ली से काफी नजदीक है और इस स्ट्रैटेजिक लोकशन का फायदा राज्य में निवेश करके निवेशक उठा सकते हैं।

इसके अलावा, 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के नेतृत्ववाला राजस्थान सरकार के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, डेनमार्क, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, तुर्की, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील, कतर, दक्षिण अफ्रीका जैसे प्रमुख देशों के राजदूतों/राजनयिकों के साथ एक राउंडटेबल की मेजबानी करेगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों और निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों दिए जा रहे में फिस्कल/नॉन-फिस्कल इन्सेंटिव्स वगैरह की जानकारी दी जाएगी।

इससे पहले, उसी दिन सुबह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाला यह प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कॉन्क्लेव में भी शामिल होगा और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) के चेयरमैन/सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा एवं उन्हें राज्य में नई परियोजनाओं पर काम करने या सहयोग के नए अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित करेगा।

मुस्लिम लॉ बोर्ड के महासचिव का आमेर में 1,400 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा- किरोड़ी लाल मीणा

कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, इसमें मंदिर माफी, सिवाय चक व पुलिस को आवंटित भूमि शामिल है

- **डॉ. किरोड़ी ने कहा, फज़ल उर रहीम ने खड़गे, अशोक गहलोत, सिद्धारमैया, सलमान खुर्शीद, शरद पवार व स्टालिन आदि के साथ मिलकर देश में अशांति व अस्थिरता फैलाने का काम किया है।**
- **उन्होंने मामले की, ई.डी. सी.बी.आई. और एस.ओ.जी. से जाँच कराने की माँग की।**

जयपुर, 30 सितंबर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फज़ल उर रहीम ने जयपुर में मंदिर माफी, सिवाय चक और पुलिस विभाग को आवंटित करीब 1400 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे ही अवैध कब्जे देश के कई राज्यों में किए हुए हैं।

किरोड़ी लाल ने कहा कि फजल उर रहीम अब कांग्रेस समेत विपक्षी राजनेताओं के साथ मिलकर संसद में पेश किये गये "वक्फ संशोधित बिल 2024" को लेकर देश में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति, जो वक्फ सहित मंदिर, ट्रस्ट एवं आदिवासियों की जमीन को बेचकर राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त है, वही व्यक्ति, एक संगठित गिरोह बनाकर वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। इस मामले की ई.डी., सी.बी.आई. और एस.ओ.जी. से जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि फज़ल उर रहीम ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद, एन.सी.पी. के शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन सहित अनेक लोगों के साथ मिलकर देशभर में नरेन्द्र मोदी के खिलाफ षडयंत्र रचकर आम मुस्लमान भाईयों को भड़काते हुए देश में अशांति और अस्थितरता फैलाने का काम किया है। एक ओर फज़ल उर रहीम द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ, ट्रस्ट और मंदिर माफी की जमीनों को हड़पा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर, खाड़ी देशों से अवैध धन प्राप्त कर देश -विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद, फज़ल उर रहीम और इसके भाई जिया उर रहीम ने कुछ लोगों के साथ मिलकर किशनपुरा, आमेर में 900 बीघा राजकीय भूमि पर कब्जा कर धर्म विशेष के लोगों की 12 अवैध कॉलोनी बसा दीं। इसके अलावा, किशनपुरा व आमेर में राजस्थान पुलिस विभाग को आवंटित 500 बीघा पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि फज़ल उर रहीम की बेटी सुल्ताना राजस्थान महिला कांग्रेस में महासचिव, दामाद मोहम्मद शोएब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में अपनी बेटी-दामाद के साथ मिलकर फज़ल उर रहीम ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया।

किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि फज़ल उर रहीम ने मंदिर माफी की जमीन पर एक दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनियां बसा दीं। इनमें कामां नगर, अशरफ कॉलोनी, जामिया नगर, कबीर नगर, इबादत नगर, मदीना नगर, हिदायत नगर, कलाम नगर, रंगरेज सिटी, एम के विहार, डायमंड नगर और स्टार सिटी शामिल हैं।

किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि फज़ल और जिया-उर-रहीम ने 2005 में फर्जी इकरारनामा के जरिए जामिया हिदायत ट्रस्ट, जयपुर और मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशनल ट्रस्ट की, जयपुर व अहमदाबाद में स्थित 18 से 20 बीघा भूमि करोड़ों रुपए में बेचकर इन पर समुदाय विशेष की अवैध कॉलोनियां बसा दीं। इन्होंने मुंबई में भी आदिवासियों की जमीन को बेचकर करोड़ों रुपए अर्जित किए। फ़ज़ल ने मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशनल ट्रस्ट व मूसा फाउण्डेशन ट्रस्ट बना कर इन ट्रस्टों के बैंक खातों में करोड़ों रूपयों का लेनदेन किया, जो कि एफ.सी.आर.ए. का उल्लघंन है।

किरोड़ीलाल मीणा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जयसिंहपुरा खोर पुलिस थाने में इनके खिलाफ, जमीनों के अवैध कब्जा करने सहित अन्य 5 मुकदमे लगाए गए, लेकिन, कांग्रेस सरकार ने इन की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। कोर्ट से इस्तेगासे के माध्यम से दर्ज मुकदमों में कार्रवाई करने की बजाय, उनमें एफ.आर. लगाकर फाइल बंद कर दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टी.टी.डी. की ओर से, वरिष्ठ एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एक ही सप्लायर द्वारा जून तथा 4 जुलाई तक सप्लाई किया गया घी विश्लेषण (जाँच) के लिये नहीं भेजा गया। यह वही घी था, जो 6 और 12 जुलाई को दो टैंकरों से प्राप्त हुआ था।

बैंच ने पूछा, "जब आपने एस.आई.टी. से जाँच कराने के आदेश दिये हैं, जो प्रैस तक जाने की क्या जरूरत थी? जब आप किसी संवैधानिक पद पर हैं, तो हम यह अपेक्षा रखते हैं कि आप भगवान को राजनीति से दूर रखेंगे.......आप को जानकारी जुलाई में मिलती है, 18 सितम्बर को आप सार्वजनिक बयान देते हैं। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं तो आपने सार्वजनिक बयान कैसे दिया?"

कोलकाता की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अभी हाल ही में, ममता ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि ट्राम-ट्रैक हाज़रा रोड जैसे आम रास्तों पर परेशानी का कारण बन गये हैं। उन्होंने कहा था कि उनके निवास-स्थान कालीघाट जाने वाली हाज़रा रोड बाइक वालों के लिये खतरनाक हो गई है। ट्राम - ट्रैक के कारण, उनके वाहनों के किसी भी क्षण फिसलने की आशंका रहती है।"

ट्राम -सेवा बन्द किये जाने के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका पहले से ही विचाराधीन है, जिसमें कहा गया है कि ट्राम 6-7 रु. प्रति व्यक्ति जैसे न्यूनतम किराये पर आवागमन सुविधा प्रदान कर रही हैं।

सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ीं: ई.डी. ने केस दर्ज किया

गत सप्ताह लोकायुक्त ने भी सिद्धारमैया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था

- **दूसरी ओर सिद्धारमैया अभी भी कह रहे हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वे इस्तीफा नहीं देंगे और कानूनी रुप से लड़ेंगे।**

नयी दिल्ली, 30 सितंबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ई.डी. ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कर्नाटक के लोकायुक्त ने राज्य के सी.एम. और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। ये मामला मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण (एम.यू.डी.ए.) भूखंड आवंटन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद केस दर्ज किया गया है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर एम.यू.डी.ए. द्वारा उनकी पत्नी बीएम पार्वती को 14 स्थलों के आवंटन में अनियमितता के आरोप हैं। आरोप है कि कर्नाटक के सी.एम. की पत्नी को 2011 में कथित तौर पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ़ से तमाम नियमों को ताक पर रखकर 14 हाउसिंग साईट दी थी। राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है और सी.एम. सिद्धारमैया का इस्तीफा मांग रही है।

लोकायुक्त द्वारा दर्ज किए गए केस में सिद्धारमैया को आरोपी नंबर एक, उनकी पत्नी बीएम पार्वती को आरोपी नंबर दो, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी को आरोपी नंबर तीन और देवराजू, जिनसे मल्लिकार्जुन स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी, उन्हें आरोपी नंबर चार बनाया गया है।

इस पूरे मामले पर कर्नाटक के सी.एम. सिद्धारमैया ने कहा है कि एम.यू.डी.ए. मुद्दे में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष उनसे डरा हुआ है। सिद्धारमैया ने साफ तौर पर कहा है कि जांच के आदेश के बावजूद भी वह सी.एम. पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। सिद्धारमैया ने कहा कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे।

महाराष्ट्र सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार ने कहा प्राचीन काल से ही गायों का मानव जीवन में एक अनूठा महत्व रहा है। वैदिक काल से गायों के धार्मिक, वैज्ञानिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए उन्हें कामधेनु कहा जाता है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में गायों की अलग-अलग देशी नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन दिन-ब-दिन देशी गायों की संख्या में भारी कमी आ रही है। देशी गायों के दूध में मानव आहार में अधिक पोषण मूल्य होता है। देशी गायों का दूध एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि इसमें मानव शरीर के पोषण के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। रिपोर्टों के अनुसार महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने देशी गायों के पालन के लिए 50 रुपये प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का निर्णय लिया है क्योंकि राज्य में गोशालाएं अपनी कम आय के कारण इसका खर्च वहन नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया।

वायु सेना के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पायलट स्ट्रीम में नियुक्त किया गया था। लगभग 40 वर्षों की लंबी सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रहे अधिकारी एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट हैं, जिनके पास रोटरी विंग विमानों पर 5,000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है।

दुनिया भर में बढ़ रही है ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है और ऊर्जा खपत भी काफी कम है। भारतीय रेल्वे अपना नैटवर्क तेजी से बढ़ाना चाहता है और ट्रेनें की संख्या भी बढ़ाना चाहता है।

वंदे भारत ट्रेन को भारतीय रेल्वे की महत्वपूर्ण टैक्नीकल उपलब्धि माना जा रहा है। यह ट्रेन आधुनिक सुविधा सम्पन्न है, जैसे वाई फाई, जी.पी.एस., स्वचालित दरवाजे और आरामदायक सीटें, जिसकी वजह से विश्व के कई देशों को इनमें रुचि पैदा हो गई है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, गत दस सालों में रेल्वे ट्रैक में 31,000 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और हमारा लक्ष्य इसमें 40,000 किलोमीटर की वृद्धि करने का है। वैष्णव ने बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनाने पर भी जोर दिया और कहा कि काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। सुरक्षा पर भी रेल्वे का पूरा ध्यान है। इसके लिए रेल्वे स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटैक्शन सिस्टम "कवच" स्थापित करने की तैयारी में है।

इसमें 40,000 किलोमीटर रेल्वे ट्रैक कवर होगा तथा 10,000 ट्रेनों में यह स्थापित होगा।

रेल मंत्री ने कहा कि कवच की स्थापना के बाद दुर्घटनाओं में 80 प्रतिशत तक कमी भी हो जाएगी और मानवीय गलतियों पर भी नज़र रखी जा सकेगी। रेल मंत्री ने कहा कि दस हजार ट्रेनों और 9,600 किलोमीटर ट्रैक के लिए टैंडर दिया जा चुका है।

मथुरा-पलवल और मथुरा-नागदा के 632 किलोमीटर लम्बे ट्रैक पर कवच स्थापित किया जा चुका है। कोटा-सवाई माधोपुर ट्रैक पर भी कवच स्थापित हो चुका है।

ट्रैक्टर से टक्कर में कार सवार चार दोस्तों की मौत

नयी दिल्ली, 30 सितंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 के पास हुए एक सड़क हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि हादसा रविवार देर रात करीब 2 बजे हुआ और पीड़ित दिल्ली के न्यू कोंडली के निवासी थे। अपर पुलिस उपायुक्त जोन प्रथम मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि सेक्टर-24 थाने की पुलिस ने हादसे में घायल हुए दिल्ली के न्यू कोंडली निवासी उत्तम की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मोदी ने इज़रायल के प्रधानमंत्री से बात की

मध्य पूर्व एशिया में बढ़ते तनाव के बीच मोदी ने शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया

- **इज़रायल द्वारा लेबनान में हिजबुल्ला के नेताओं और ठिकानों पर हमले लगातार जारी हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बाइडन ने कहा है कि पूर्ण युद्ध से बचना चाहिये।**

नयी दिल्ली, 30 सितंबर। मध्य पूर्व एशिया में तनाव इस वक्त चरम सीमा पर है। एक ओर इज़रायल है तो दूसरी ओर हमास, हिजबुल्लाह, यमन के हूती और फिर ईरान। इज़रायल की ओर से एक के बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।

हाल ही में इज़रायल ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को भी मार गिराया है जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे समय में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। पीएम मोदी ने खुद इस बारे में ट्वीट कर के जानकारी साझा की है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर के जानकारी दी है कि उन्होंने पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम के बारे में इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है।

पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है।

क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दूसरी ओर इजरायल लेबनान में हिजबुल्ला के नेताओं और उसके ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार हमले कर रहा है। इज़रायल ने मध्य बेरूत में हवाई हमले किए हैं। खास बात ये है कि एक साल के संघर्ष में मध्य बेरूत में यह इजरायल का पहला हवाई हमला है।

वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रविवार को कहा है कि वह इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। बाइडन का मानना है कि पश्चिम एशिया में पूर्ण युद्ध से बचा जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह नेतन्याहू से कब बात करेंगे।

बी.एस.एफ. ने 9 माह में 153 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े

जालंधर, 30 सितंबर। सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) पंजाब ने पिछले नौ महीनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी संख्या में पाकिस्तानी ड्रोन, हेरोइन और घुसपैठियों को पकड़ा है।

बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के जनसंपर्क अधिकारी ने सोमवार को बताया कि बीएसएफ ने पिछले नौ महीनों में 153 से अधिक अवैध पाकिस्तानी ड्रोन, 190 किलोग्राम हेरोइन, 29 हथियार और 400 राउंड गोला-बारूद जब्त करके देश की सीमाओं की सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ के जवानों के सतर्क प्रयासों से 153 व्यक्तियों को भी पकड़ा गया।

इलैक्टोरल बॉण्ड वसूली मामले में निर्मला सीतारमण को राहत मिली

कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर मुकदमे में जाँच पर रोक लगाई

- **जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नलीन कुमार कटील को आरोपी बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि चुनावी बॉण्ड की आड़ में 8,000 करोड़ रूपये का फायदा उठाया गया है।**

नयी दिल्ली, 30 सितंबर। इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राहत मिल गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ मामले में जांच पर रोक लगा दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली मामले में उनके खिलाफ दायर मुकदमे पर 22 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है।

कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलीन कुमार कटील ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 22 अक्टूबर तक कर्नाटक के पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कटील के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की जांच पर रोक लगा दी है।

इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली मामले में नलीन कुमार कटील सह-आरोपी हैं। इसी मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी बांड की आड़ में कुछ कंपनियों से जबरन वसूली की थी।

जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने निर्मला सीतारमण और नलीन कुमार कटील को आरोपी बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने चुनावी बॉण्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का फायदा उठाया। शिकायत में कहा गया कि सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की गुप्त सहायता और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों के फायदे के लिए हजारों करोड़ रुपये की जबरन वसूली की। आदर्श आर अय्यर के अनुसार चुनावी बॉण्ड की आड़ में जबरन वसूली का काम विभिन्न स्तरों पर भाजपा के पदाधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने फरवरी में चुनावी बॉण्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि इससे सूचना के अधिकार और संविधान के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉण्ड योजना को असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमानी' करार देते हुए 15 फरवरी को एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए बॉण्ड का पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपे।

न्यायालय ने आयोग को संबंधित विवरण 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908